फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन	12051.00	815.00	815.00	815.00	11236.00
योग-	**12051.00**	**815.00**	**815.00**	**815.00**	**11236.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल 29-अनुरक्षण	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00
योग रू0 :	**0.00**	**815.00**	**815.00**	**815.00**	**815.00**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए शासनादेश संख्या-77/तीस-3-2019, दिनांक 09-01-2019 द्वारा 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं अन्य जनपदों में एक-एक ट्रिब्युनल अर्थात कुल 75 ट्रिब्युनल को क्रियान्वित किया जाना है।

अत: लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन मद में रू0 815.00 लाख की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के निर्देशानुसार 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं अन्य जनपदों में एक-एक ट्रिब्युनल अर्थात कुल 75 ट्रिब्युनल कार्यालयों को क्रियान्वित किया जाना है।

लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल-29-अनुरक्षण में कार्यालय के रिन्यूवेशन, मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु कुल रू0 500.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के कार्यालय संचालन हेतु लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के अन्तर्गत वाहनों को किराये पर लिये जाने हेतु मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 35 हजार प्रति वाहन प्रति माह की दर से एक वर्ष हेतु कुल रू0 315.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 004 /ई-9-यू0ओ0-817 /दस-2019, दिनॉक 24 अप्रैल, 2019

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-31/2019/1028/तीस-3-19-06बी/2014टीसी-1, दिनॉक 25 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in